नईदुनिया

नेपाल में सांप्रदायिक हिंसा फैली, तीन लोगों की मौत

काठमांडू, एजेंसीः नेपाल के पूर्वी सीमावर्ती जिलों में दो समुदायों के बीच शुरू हुई सांप्रदायिक हिंसा अब तराई क्षेत्र के कई अन्य हिस्सों तक फैल गई है। हिंसा में मरने वालों की संख्या बढ़कर तीन हो गई है। स्थिति को देखते हुए भारत-नेपाल सीमा से सटे सुनसरी, सप्तरी, सिराहा और धनुषा जिलों में कर्फ्यू लगाया गया है, जबकि पर्सा जिले में निषेधाज्ञा लागू की गई है।

हालात को नियंत्रित करने के लिए नेपाल पुलिस, सशस्त्र प्रहरी बल और नेपाली सेना की बड़ी टुकड़ियां तैनात की गई हैं। हिंसा की शुरुआत रविवार रात सुनसरी जिले में दो समुदायों के बीच हुई झड़प से हुई थी। इस घटना में एक युवक की गोली लगने से मौत हो गई थी।

इसके बाद अशांति के दौरान गंभीर रूप से घायल एक अन्य युवक ने गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। वहीं, सिराहा जिले के गोलबाजार में प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई झड़प में गोली लगने से 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई।

प्रदर्शनकारियों ने गुरुवार सुबह भारत-नेपाल संपर्क के लिए महत्वपूर्ण पूर्व-पश्चिम राजमार्ग को जाम कर दिया। इसके बाद विरोध प्रदर्शन गोलबाजार तक फैल गया, जहां कई दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में तोड़फोड़ और आगजनी की गई।

हिंसा के दौरान हथियारों से लैस समूहों के सड़कों पर उतरने से तनाव और बढ़ गया। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षा बलों ने लाठीचार्ज किया और 21 राउंड आंसू गैस के गोले छोड़े।

सिराहा पुलिस के प्रवक्ता ने स्थिति को तनावपूर्ण बताया है। उन्होंने कहा कि फिलहाल प्राथमिकता शांति और कानून-व्यवस्था बहाल करना है।

गंगा का पानी हाईवे तक पहुंचा, 7 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट

गुजरात और उत्तराखंड में स्कूल बंद, राजस्थान में गर्मी का असर जारी

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः देश के कई हिस्सों में मौसम का अलग-अलग असर देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश में मानसून कमजोर पड़ने के बावजूद पहाड़ी क्षेत्रों में हो रही भारी बारिश के कारण गंगा, घाघरा-सरयू समेत करीब 10 नदियां उफान पर हैं। बिजनौर में गंगा का पानी बहसूमा-ठाकुरद्वारा स्टेट हाईवे के ऊपर से बह रहा है। गुजरात में खराब मौसम को देखते हुए शुक्रवार को सभी स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई। वहीं, उत्तराखंड के बागेश्वर और रुद्रप्रयाग जिलों में भी मौसम की स्थिति को देखते हुए स्कूल बंद रखे गए हैं। दूसरी ओर, पश्चिमी राजस्थान में गर्मी का असर बढ़ गया है। जैसलमेर और बाड़मेर में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम में इस बदलाव की वजह पश्चिम दिशा से आ रही गर्म हवाओं को बताया जा रहा है।

मध्य प्रदेश में मानसून के तीन स्ट्रॉन्ग सिस्टम सक्रिय हैं। इसके कारण अगले दो दिनों तक प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। इसके अलावा राजस्थान, बिहार समेत सात राज्यों में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। देश के कई अन्य हिस्सों में भी बारिश से नुकसान की खबरें सामने आई हैं। राजस्थान के चूरू जिले के सरदारशहर में तेज बारिश के कारण बाजार की सड़कों पर करीब तीन फीट तक पानी भर गया। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में उदंती नदी पर निर्माणाधीन पुल गिर गया। उत्तर प्रदेश के बलिया में सरयू नदी के कटाव से दो मकान नदी में समा गए हैं, जबकि कई अन्य मकानों पर खतरा बना हुआ है। झारखंड में लगातार बारिश के कारण खेतों में धान की रोपाई तेज हो गई है। उत्तराखंड के हरिद्वार में सूखी नदी में अचानक पानी बढ़ने से एक कार फंस गई।

कराची में गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई पर जानलेवा हमला

कराची, एजेंसीः पाकिस्तान के कराची शहर के ल्यारी इलाके में जेल में बंद कुख्यात गैंगस्टर उजैर बलोच के भाई जुबैर बलोच पर जानलेवा हमला हुआ है। गुरुवार शाम बाइक सवार अज्ञात हमलावरों ने उनके घर के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। हमले में 40 वर्षीय जुबैर बलोच गंभीर रूप से घायल हो गए। गोलीबारी की चपेट में आए दो राहगीर भी घायल हुए हैं। जुबैर के सीने और पेट में गोलियां लगी हैं। उन्हें कराची के सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां उनकी सर्जरी की गई। अस्पताल प्रशासन के अनुसार, एक अन्य घायल की हालत भी गंभीर बनी हुई है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि हमलावरों की पहचान और उनके भागने के रास्ते का पता लगाया जा सके। मौके से बरामद गोलियों के खोल फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। हमले के बाद ल्यारी इलाके में तनाव बढ़ गया है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए अतिरिक्त पुलिस बल और रेंजर्स तैनात किए गए हैं। कराची के प्रवेश और निकास मार्गों पर भी जांच तेज कर दी गई है।

समझौते से सऊदी अरब की क्षेत्रीय भूमिका और अमेरिका के साथ संबंध होंगे मजबूत

ट्रम्प का दावाः हमास और इजराइल में शांति समझौता, गाजा से हटेगी सेना

वॉशिंगटन, एजेंसीः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने दावा किया है कि गाजा में हमास और इजराइल के बीच एक बड़ा शांति समझौता हुआ है। ट्रम्प के अनुसार, हमास और अन्य हथियारबंद संगठनों ने हथियार छोड़ने पर सहमति जताई है। इसके बाद इजराइली सेना गाजा से चरणबद्ध तरीके से पीछे हटेगी। ट्रम्प ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता उनकी 20 पॉइंट गाजा योजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है और गाजा में स्थायी शांति तथा सुरक्षा की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा।

ट्रम्प के अनुसार, समझौता कई चरणों में लागू किया जाएगा। पहले हमास को अपने हथियार छोड़ने होंगे। इसके बाद इजराइली सेना धीरे-धीरे गाजा से हटेगी। सेना की वापसी के बाद एक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स और नई फिलिस्तीनी पुलिस गाजा की सुरक्षा व्यवस्था संभालेंगे। बताया गया कि हमास के हथियार छोड़ने की मंजूरी के बाद 14 दिन की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें समझौते के अलग-अलग चरणों को लागू करने की समयसीमा तय की जाएगी।

एक अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान ने हमास को इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करने की सलाह दी थी। हालांकि, अधिकारी के अनुसार बदलते हालात और गाजा के लोगों के हितों को देखते हुए हमास ने समझौते को स्वीकार करने का फैसला किया।

समझौते को लागू करने में कई चुनौतियां भी सामने हैं। इनमें हमास और अन्य गुटों का हथियार छोड़ना, इजराइली सेना की वापसी, नई सुरक्षा व्यवस्था बनाना और नई फिलिस्तीनी सरकार को स्थानीय तथा अंतरराष्ट्रीय समर्थन दिलाना शामिल है।

इसके अलावा जमीन पर समझौते को लागू करने की प्रक्रिया में कई महीने लग सकते हैं। हथियारों की जांच, सेना की वापसी, प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा तंत्र तैयार करने जैसे कार्य चुनौतीपूर्ण होंगे।

ट्रम्प ने गाजा युद्ध खत्म करने की योजना में बोर्ड ऑफ पीस का भी प्रस्ताव रखा था। इस बोर्ड का उद्देश्य केवल गाजा तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वैश्विक स्तर पर संघर्षों को सुलझाने में भूमिका निभाना होगा। चार्टर के अनुसार, तीन साल से अधिक समय तक सदस्य बने रहने वाले देशों को एक अरब डॉलर का योगदान देना होगा।

जमीनी नवाचार देश की जरूरतों के अनुकूलः राष्ट्रपति मुर्मु

अटल इनोवेशन मिशन के नवाचारकर्ताओं से मिलीं राष्ट्रपति, स्थानीय समाधानों की सराहना

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने कहा है कि जमीनी स्तर के नवाचार देश की जरूरतों के लिए अधिक अनुकूल होते हैं। इनमें स्थानीय अनुभव, वैज्ञानिक सोच, व्यक्तिगत सृजनशीलता और सामाजिक उत्तरदायित्व का समावेश होता है। राष्ट्रपति भवन सचिवालय के अनुसार, राष्ट्रपति मुर्मु ने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में अटल इनोवेशन मिशन के जमीनी स्तर के नवाचारकर्ताओं के समूह से मुलाकात की। उन्होंने मिशन की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया और नवाचारकर्ताओं से उनके प्रयासों के बारे में जानकारी ली।

राष्ट्रपति ने कहा कि भारत अपनी व्यापक क्षमता और नवाचार की भावना के आधार पर जमीनी नवाचार के क्षेत्र में विश्व की बड़ी शक्ति बन सकता है। उन्होंने कहा कि देशभर में नवाचारकर्ता स्थानीय समस्याओं के ऐसे समाधान तैयार कर रहे हैं, जिनका महत्व राष्ट्रीय स्तर पर भी है। उन्होंने बताया कि प्रदर्शनी में अपशिष्ट पदार्थों से उपयोगी उत्पाद बनाने, ऊर्जा संरक्षण, महिलाओं और दिव्यांगजनों की सुविधा बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण, कृषि और कला संरक्षण जैसे क्षेत्रों में किए गए नवाचार प्रदर्शित किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि समाज में बदलाव केवल विचारों से नहीं आता, बल्कि उन विचारों को आगे बढ़ाने के लिए सही माहौल, मार्गदर्शन और संसाधनों की जरूरत होती है। उन्होंने अटल कम्युनिटी इनोवेशन सेंटर्स की भूमिका की सराहना की, जो नवाचारकर्ताओं को तकनीकी सहायता और उद्यम विकसित करने के अवसर उपलब्ध करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी पूरा होगा, जब प्रत्येक नागरिक नई सोच के साथ समस्याओं के समाधान के लिए आगे आए।

20 से अधिक भारतीयों की वापसी के लिए बातचीत जारी

रूसी सेना में फँसे 139 भारतीय नागरिकों को छुड़ा लिया गयाः विदेश मंत्रालय

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत ने कहा है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से रूसी सेना में मजबूरी में काम कर रहे 139 भारतीय नागरिकों को वापस लाया जा चुका है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि 20 से अधिक भारतीय नागरिक अभी भी वहां फंसे हुए हैं और उनकी वापसी के लिए बातचीत जारी है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि सरकार रूसी सेना में शामिल भारतीय नागरिकों के मामलों को गंभीरता से देख रही है। उन्होंने भारतीय नागरिकों से जोखिम भरे और फर्जी नौकरी के प्रस्तावों से सावधान रहने की अपील की। अमेरिका से वापस भेजे गए भारतीय नागरिकों के बारे में प्रवक्ता ने बताया कि वर्ष 2025 से अब तक करीब 5 हजार भारतीय नागरिकों को वापस भेजा गया है। इनमें वर्ष 2026 में अब तक 1273 और वर्ष 2025 में 3567 भारतीय नागरिक शामिल हैं। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय निर्वासन से पहले संबंधित व्यक्तियों की व्यापक जांच कर उनकी भारतीय नागरिकता की पुष्टि करता है। अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जारी है। रूस से तेल खरीद पर अमेरिका की ओर से संभावित टैरिफ के सवाल पर जायसवाल ने कहा कि भारत स्थिति पर नजर बनाए हुए है। उन्होंने कहा कि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए विभिन्न स्रोतों पर निर्भर करता है और अपने नागरिकों के हितों को ध्यान में रखते हुए कदम उठाता है। उन्होंने यह भी बताया कि अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी करने वाले विदेशी छात्रों से जुड़ी फीस और आव्रजन नियमों में बदलाव के प्रभावों को लेकर संबंधित सरकारों के साथ बातचीत की जा रही है।

पीएम-किसान योजना 2030-31 तक जारी रहेगी, सरकार ने मंजूर किए 3.15 लाख करोड़

किसानों को हर साल 6 हजार रुपये की सहायता जारी, डीबीटी के जरिए सीधे खाते में पहुंचेगी राशि

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) योजना को वर्ष 2030-31 तक जारी रखने का फैसला किया है। इसके लिए 3.15 लाख करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय को मंजूरी दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

योजना के तहत पात्र भू-स्वामी किसान परिवारों को हर साल 6 हजार रुपये की आर्थिक सहायता तीन समान किस्तों में सीधे बैंक खातों में भेजी जाती है। सरकार ने किसानों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से फरवरी 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि किसानों की समृद्धि ही राष्ट्र की समृद्धि की आधारशिला है। उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली के माध्यम से किसानों को समयबद्ध और पारदर्शी तरीके से आय सहायता दी जा रही है, जिससे कृषि निवेश और आजीविका को मजबूती मिल रही है। उन्होंने बताया कि आधार प्रमाणीकरण, डिजिटल सत्यापन और मजबूत डीबीटी व्यवस्था के कारण पीएम-किसान योजना पारदर्शिता और जवाबदेही का उदाहरण बनी है। अब तक योजना की 23 किस्तों के माध्यम से किसानों के खातों में 4.47 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उन्होंने कहा कि 23वीं किस्त में 9.49 करोड़ से अधिक किसानों को 18,984 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दी गई। कोविड-19 महामारी के दौरान किसानों को 1.71 लाख करोड़ रुपये से अधिक की आर्थिक मदद उपलब्ध कराई गई। वहीं, महिला किसानों को 1.06 लाख करोड़ रुपये से अधिक की सहायता मिली है।

सरकार के अनुसार, योजना से किसानों को बीज, उर्वरक, सिंचाई, कृषि मशीनरी और अन्य जरूरतों के लिए समय पर निवेश करने में मदद मिली है। नीति आयोग के विकास निगरानी एवं मूल्यांकन कार्यालय के आकलन में भी योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। सरकार ने कहा कि योजना को आगे जारी रखने से किसानों की निवेश क्षमता बढ़ेगी, कृषि उत्पादकता में सुधार होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

प्रस्ताव *2030-31 तक चलेगी योजना, घरेलू ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता पर जोर...*

गहरे समुद्र में तेल और गैस खोज के लिए 84 हजार करोड़ की योजना

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गहरे समुद्र में तेल और गैस के अन्वेषण को बढ़ावा देने के लिए 84,084 करोड़ रुपये की समुद्र मंथन योजना को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिमंडल बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई।

सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की इस योजना को वित्त वर्ष 2030-31 तक लागू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि देश में गैस और पेट्रोलियम उत्पादों की बढ़ती मांग को देखते हुए यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी।

उन्होंने बताया कि समुद्र मंथन योजना के दो प्रमुख हिस्से होंगे। पहले चरण में भारतीय समुद्री सीमा के गहरे क्षेत्रों में तेल और गैस भंडार की पहचान के लिए आंकड़े जुटाए जाएंगे। दूसरे चरण में इन संसाधनों के उत्पादन और निकासी का कार्य किया जाएगा।

योजना के तहत आंकड़े जुटाने के लिए 28,500 करोड़ रुपये और तेल एवं गैस निकालने की प्रक्रिया के लिए 43,200 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लंबित परियोजनाओं को गति देने के लिए सरकार 10 हजार करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देगी। इस राशि

का उपयोग साझा अवसंरचना विकास के लिए किया जाएगा।

सरकार 2 हजार करोड़ रुपये की लागत से तेल एवं गैस विनिर्माण और सेवा क्षेत्र के लिए जोन भी विकसित करेगी। योजना के तहत उच्च गुणवत्ता वाले भूकंपीय आंकड़ों का संग्रह, गहरे और अति-गहरे समुद्री क्षेत्रों में खोजी ड्रिलिंग, नए समुद्री बेसिनों में वैज्ञानिक ड्रिलिंग और अपतटीय उत्पादन से जुड़ी सुविधाओं का विकास किया जाएगा।

सरकार के अनुसार, समुद्र मंथन योजना से करीब 60 करोड़ टन कच्चे तेल और गैस के भंडार मिलने की संभावना है। इससे घरेलू तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने, रोजगार के नए अवसर पैदा करने और मेक इन इंडिया तथा आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूती मिलने की उम्मीद है।

योजना के माध्यम से भारत अपतटीय प्रौद्योगिकी और ऊर्जा क्षेत्र में वैश्विक प्रतिस्पर्धी केंद्र के रूप में उभरने की दिशा में आगे बढ़ेगा। इससे अन्वेषण और उत्पादन क्षेत्र में बड़े निवेश आकर्षित होने की संभावना है।

भारत भूटान को देगा 4 हजार करोड़ रुपये की रियायती ऋण सुविधा

नईदुनिया ब्यूरो, नई दिल्लीः भारत और भूटान ने द्विपक्षीय विकास सहयोग को मजबूत करने के लिए गुरुवार को पांचवीं भारत-भूटान विकास सहयोग वार्ता आयोजित की। इस दौरान भारत ने भूटान को 4,000 करोड़ रुपये की रियायती ऋण सुविधा उपलब्ध कराने पर सहमति जताई। वार्ता में दोनों देशों ने विकास परियोजनाओं की प्रगति और उनके प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा की। बैठक की सह-अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री और भूटान के विदेश सचिव दाशो पेमा लेक्टुप दोर्जी ने की। बैठक में भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना के तहत भारत के सहयोग से चल रही विभिन्न विकास परियोजनाओं पर चर्चा हुई। भारत ने भूटान के विकास कार्यों के लिए रियायती ऋण सुविधा देने की घोषणा की। दोनों देशों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में नई साझेदारी बढ़ाने पर भी सहमति जताई। इसके अलावा ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारत ने भूटान की शाही सरकार को 45 इलेक्ट्रिक वाहन सौंपे। वार्ता के दौरान पर्यावरण संरक्षण और टिकाऊ विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर भी चर्चा हुई। भारत की सहायता से विकसित थिम्फू इकोलॉजिकल पार्क और ओलाखा पार्क का वर्चुअल उद्घाटन दोनों देशों के विदेश सचिवों ने किया।